MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Kalpana Saini: Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Shri Mayankbhai Jaydevbhai Nayak (Gujarat), Shri Mahendra Bhatt (Uttarakhand), Smt. S. Phangnon Konyak (Nagaland), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Babubhai Jesangbhai Desai (Gujarat), Shri Aditya Prasad (Jharkhand), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia (Gujarat), Shri Devendra Pratap Singh, (Chhattisgarh), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya, (Gujarat), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Mission Ranjan Das (Assam), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Shri Jose K. Mani (Kerala), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Smt. Ramilaben Becharbhai Bara, (Gujarat), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sujeet Kumar, (Odisha).

Shrimati Priyanka Chaturvedi; not present. Dr. Medha Vishram Kulkarni, 'Demand to connect Pune with high speed trains.'

Demand to connect Pune with high speed trains

डा.मेधा विश्राम कुलकर्णी (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, मैं आपका ध्यान पुणे की रेल कनेक्टिविटी की समस्या और हाई स्पीड ट्रेन की मांग की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ।

पुणे देश में सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, जिसे विद्या की नगरी या शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है। पुणे एक आईटी हब है, पुणे औद्योगिक और ऐतिहासिक नगरी भी है। पुणे बहुत ही तेजी से विकसित होने वाला शहर है, लेकिन माननीय महोदय, पुणे से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद जैसे प्रमुख महानगरों तक राजधानी, तेजस और वंदे भारत जैसी उच्च गति ट्रेनें उपलब्ध नहीं हैं। इससे व्यापारियों, छात्रों और यात्रियों को काफी असुविधा होती है। अगर पुणे से दिल्ली की ट्रेन की बात करें, तो वर्तमान में जो ट्रेनें उपलब्ध हैं, उनमें झेलम एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस प्रमुख हैं। ये ट्रेनें यह फासला 26 से 28 घंटे में तय करती हैं, जिससे काफी समय व्यर्थ होता है। पुणे से सीधी राजधानी ट्रेन उपलब्ध नहीं है, जिससे यात्रियों को पहले मुंबई जाकर राजधानी पकड़नी पड़ती है। इससे यात्रा का समय और खर्च, दोनों बढ़ जाते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और पुणे भारत के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। इसलिए, मेरी विनती है कि दिल्ली से बेंगलुरु या दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली राजधानी ट्रेनों को प्रतिदिन या सप्ताह में तीन बार पुणे होते हुए चलाया जाए।

मेरी दूसरी मांग यह है कि पुणे से कोलकाता के लिए वर्तमान में सबसे तेज़ ट्रेन हावड़ा आज़ाद हिंद एक्सप्रेस है, जो यह सफर 28 घंटे में तय करती है। इस रूट पर वंदे भारत या तेजस जैसी हाई-स्पीड ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

तीसरी मांग यह है कि चेन्नई और हैदराबाद दोनों ही महत्वपूर्ण आईटी हब हैं, लेकिन पुणे से चेन्नई के बीच तेजस या वंदे भारत जैसी कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं है। इसी तरह, पुणे-हैदराबाद मार्ग पर भी वंदे भारत जैसी कोई ट्रेन नहीं है, जबकि वर्तमान में उपलब्ध ट्रेनें यह सफर 22 घंटे में तय करती हैं। इसलिए, मैं यह मांग करती हूं।

इसके अलावा, महाराष्ट्र में कई ऐसे शहर हैं, जैसे नासिक एक महत्वपूर्ण तीर्थ और कृषि क्षेत्र है, लेकिन यहां के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं है। यात्रियों को पहले मुंबई जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है या फिर सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें लगभग 6 घंटे लगते हैं। इसलिए, मैं अनुरोध करती हूं कि पुणे से दिल्ली और पुणे-नासिक के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू की जाए।

अंत में, 'भारत गौरव ट्रेन योजना' के तहत पुणे को प्रमुख तीर्थ स्थलों से जोड़ने वाली विशेष ट्रेनें चलाई जाएं। मेरी विनती है कि मेरी इन रेल संबंधी मांगों को प्राथमिकता दी जाए। धन्यवाद!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Medha Vishram Kulkarni: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra).

Dr. John Brittas; Concern over opening up the country's offshore sand blocks for mining by private entities.

Concern over opening up the country's offshore sand blocks for mining by private entities

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, this is to bring to the notice of the House, the alarming situation that has arisen on account of the Union Government's decision for off-shore mining in the coastal belt of Kerala. The entire Kerala is agitated. The Assembly passed a unanimous resolution requesting the Government of India to withdraw the decision. I will explain to you the rationale of it. The Government's proposal is Rs. 35,000 crore of offshore sand mining project. In Kollam alone, that is, Quilon, Government intends to extract sand worth Rs. 14,200 crores. The interesting part is that Kerala Government had sent its reservations to oppose the project and said that it will have far-reaching impact on the lives and livelihood of the people. Further, the environmental impact of this mining could even devastate vast chunks of land in Kerala. Sir, you will be surprised that not even a single appropriate study on the environmental or the social side has been done by the Government of India. They simply relied on some geological survey saying that sand is available in off-shore.